मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयुष विभाग नया इतिहास लिख रहा है: दीपेंद्र चौधरी

उत्तराखंड बनेगा फिल्म निर्माण का हब: बंशीधर तिवारी

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 06 | मूल्य 15 रुपये | 29 जून-05 जुलाई, 2025

पहले रुका, अब फिर बजा पंचायत का चुनावी बिगुल

HNB UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY DEHRADUN

प्रकाशन का गौरवशाली 15वाँ वर्ष

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सच पर

GOVERNMENT DOON MEDICAL COLLEGE DEHRADUN

DOCTOR OF THE YEAR

Sacrifice • Penance • Service

2025

On the Occasion of
National Doctors' Day Celebration 2025

4th Felicitation Ceremony for

Doctor of the Year Award- 2025

"Saluting the real heroes in white coats.
Happy Doctor's Day to the saviors of health and life!"

CHIEF GUEST

Dr. Dhan Singh Rawat

Hon'ble Minister for Health & Medical Education,
Higher Education & School Education, Govt. of Uttarakhand

Venue: Govt. Doon Medical College Auditorium, Patelnagar, Dehradun

वर्ष 15 | अंक 06

दिव्य हिमगिरि

29 जून-05 जुलाई, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

बंदूक के शोर में दबी शांति की पुकार

दुनिया के करीब उनसठ देश किसी न किसी रूप में संघर्षरत हैं। उनमें केवल अपनी ताकत दिखाने की कोशिशें अधिक देखी जा रही हैं। पर, ऐसी स्थितियों को रोकने के मकसद से गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब जैसे अप्रासंगिक हो गई है। इसके चलते दुनिया भर में किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति की खबर निश्चित रूप से अच्छी बात है। युद्ध को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस युद्ध विराम की सूचना पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उनका दावा है कि उन्हीं के समझाने पर दोनों देश जंग की राह छोड़ने पर तैयार हुए हैं। पिछले बारह दिनों से दोनों देश एक-दूसरे पर विनाशकारी हमले कर रहे थे। हालांकि अमेरिका शुरू से कहता रहा कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। मगर उसका रुख एकतरफा ही था। वह स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा था। इजराइल को उसका समर्थन पिछले रविवार को तब पूरी तरह स्पष्ट हो गया, जब उसके बंकरभेदी विमानों ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर भीषण बम बरसा दिए। उस समय माना जाने लगा कि यह जंग लंबी चलेगी। युद्ध विराम की सूचना ने दुनिया को सुखद आश्चर्य से भर दिया। मगर इसके साथ ही युद्ध विराम के उल्लंघन से एक बार फिर चिंता पैदा हुई है। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल अब थक चुका है और ईरान के हमलों को नाकाम करने में किल हो रहा है, इसलिए वह कदम पीछे खींचना चाहता है। फिर, अमेरिका को भी लग रहा था कि अगर वह इराक की तरह ईरान में भी फंस गया, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। युद्ध शुरू करना तो आसान होता है, पर उसे समाप्त करना अपने हाथ में नहीं होता। फिर, किसी भी युद्ध के लंबे समय तक चलते रहने का असर न केवल संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था पर, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों पर पड़ता है। ऐसे में, इस युद्ध विराम की घोषणा हर तरह से सराहनीय कही जा सकती है। इस युद्ध में कौन सही था, कौन गलत, इसका विश्लेषण तो बहुत हो चुका, इतिहास में भी होता रहेगा, पर अभी इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि यह विराम स्थायी रूप कैसे ले। विडंबना यह है कि ट्रंप के युद्ध विराम की खबर देने के बाद भी ईरान और इजराइल ने एक-दूसरे के ठिकानों पर बम फेंके और अभी वे एक-दूसरे को संघर्ष विराम के उल्लंघन का दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। इससे यही लगता है कि दोनों के भीतर टीस अभी बनी हुई है। इसे भी समाप्त होना चाहिए। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ऐसा वातावरण बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर अधिक है। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि युद्ध में नियम-कायदों और सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया जा रहा है। इजराइल इतने समय से फिलिस्तीन में जिस तरह बम बरसा रहा है, उसमें निरपराध स्त्रियों, बच्चों तक की चिंता नहीं की गई, अस्पतालों में बीमार और घायलों की परवाह किए बिना बम गिराए गए, वह युद्ध अपराध की ही श्रेणी में आता है। फिर ईरान के विरुद्ध परमाणु हथियार बनाने के सबूत के बगैर उसने हमला कर दिया। परमाणु विकिरण की परवाह किए बिना अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिरा दिए। अमेरिका महाबली है और अब उस पर यह जिम्मेदारी सबसे अधिक है कि युद्ध की स्थितियों को टालने और रोकने के व्यावहारिक उपाय तलाश करे।

कुँवर राज अस्थाना

हिंदी के विरूद्ध बेसुरी आवाजें!

भारतीय भाषाओं का आपसी संघर्ष अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ें और मजबूत करेगा

प्रो. संजय द्विवेदी

भरोसा नहीं होता कि महाराष्ट्र जैसी समावेशी और महान धरती से हिंदी के विरोध में भी कोई बेसुरी आवाज़ सामने आएगी। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र में पहली से लेकर पाँचवीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध किया है। यह एक ऐसा विचार है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं और जानता हूं कि आज की हिंदी को स्थापित करने के लिए बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, पं. माधवराव सप्रे, रामकृष्ण खाडिलकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे जैसे यशस्वी पत्रकारों का खास योगदान है। महाराष्ट्र समन्वय और सद्भाव की धरती है, जहां सभी विचारों, भाषाओं, सामाजिक आंदोलनों को फलने-फूलने का मौका मिला है। छत्रपति शिवाजी जहां सुशासन के राष्ट्रीय प्रतीक बने, तो संत परंपरा ने महाराष्ट्र को आध्यात्मिक ऊंचाई दी, मुंबई जहां कांग्रेस की स्थापना का गवाह बना तो दूसरी नागपुर से बाबा साहब आंबेडकर और डा. केशवराम बलिराम हेडगेवार ने ऐतिहासिक आंदोलनों और संगठनों का सूत्रपात किया। मुंबई, नागपुर जैसे शहर अपनी बहुभाषिकता के कारण पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहे।

भाषा और मूल्यों को लेकर जिस तरह के विमर्श और चर्चाएं इन दिनों हवा में हैं, वह कई बार बहुत आतंकित करती हैं। अँगरेज़ी के बढ़ते साम्राज्यवाद के बीच हमारी बोलियाँ और भाषाएं जिस तरह सहमी व सकुचाई हुई सी दिखती हैं, उसमें ऐसे विचार अँगरेज़ी के प्रभुत्व को ही स्थापित करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर संदेश यह है कि आइए हम भारतीय भाषा परिवार के लोग आपस में सिर फुटौव्वल करें, एक-दूसरे के कपड़े फाड़ें और अँगरेज़ी को राजरानी की तरह प्रतिष्ठित कर दें। भारतीय भाषाओं का आपसी संघर्ष किसे ताकत दे रहा है कहने की जरूरत नहीं है। किंतु राजनीति भाषा, जाति, पंथ और क्षेत्र के नाम पर बांटने का व्यापार बन गयी है। कभी दक्षिण भारतीयों, कभी उत्तर भारतीयों के विरूद्ध अभियान चलाने वाली शिवसेना आज भाषा के नाम पर बंटवारे की राजनीति में लगी है।

विभाजनों का सुख लेती राजनीति

भारतीय भाषा परिवार की भाषाएं और बोलियाँ एक-दूसरे से टकरा रही हैं। राजनीतिक आधार पर विभाजन करके अपनी राजनीति चलाने वाली ताकतें भाषा का भी ऐसा ही इस्तेमाल कर रही हैं। देश का विचार और हमारी सामूहिक संस्कृति का विचार लुप्त होता जा रहा है। भाषा, क्षेत्र, जाति, पंथ ऐसे अखाड़े बन गए हैं, जिसने हमारी सामूहिकता को नष्ट कर दिया है। राजनीति इन्हीं विभाजनों का सुख ले रही है। कितना अच्छा होता कि शिवसैनिक अँगरेज़ी को हटाने की बात करते, लेकिन उन्हें हिंदी से ही समस्या नज़र आई। हिंदी भारतीय भाषा परिवार की बहुप्रसारित भाषा है। यह हमारे लोक जीवन में पैठी हुई है। हिंदी के ख़िलाफ़ किसी भी भाषा को खड़ा करना एक ऐसा अपराध है, जिसके लिए हमें पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी। यह अपने पुरखों के यश को बिसरा देने जैसा है, अपने अतीत को अपमानित और लांछित करने जैसा है। स्वयं को राष्ट्रवादी और हिंदूवादी बताने वाले क्षेत्रीयता के आवेश में इस कदर आँखों पर पट्टियाँ बाँध लेंगे, इसकी कल्पना भी डरावनी है। जिस तरह अँगरेज़ी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को पददलित किया है उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आज जबकि बाज़ारवाद की तेज़ हवा में हमारी तमाम बोलियाँ, तमाम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लोकगीत नष्ट होने के कगार पर हैं, क्या इन्हें बचाना और साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हिंदी और मराठी सगी बहनों की तरह विकसित हुई हैं। मराठी का साहित्य, रंगमंच, सिनेमा, अध्यात्म सब हिंदी भाषियों के प्रेरित करता रहा है। हिंदी इलाके में हो रहे 'जाणता राजा' के मंचन इस बात के गवाह हैं कि महाराष्ट्र की संस्कृति किस तरह हिंदी इलाकों में स्वीकृति पा रही है। हिंदी इलाकों से चुने गए सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि इसकी गवाही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के अनेक क्षेत्रों का मराठी भाषी शासकों ने नेतृत्व किया। राजनीति से लेकर साहित्य और समाज सेवा में अपना अग्रणी स्थान बनाया। आप देखें तो रानी अहिल्याबाई होलकर, जो एक हिंदी भाषी इलाके की शासिका थीं, उन्हें पूरे देश में किस तरह याद किया गया। भारत का विचार कृतित्व को सम्मान देने का रहा है। इसलिए अनेक मराठी भाषी राजनेता, लेखक, कलाकार हिंदी भाषी क्षेत्रों में सम्मान पाते रहे। ताजा उदाहरण में इंदौर से सुमित्राताई महाजन आठ बार लोकसभा का चुनाव जीतीं। कृष्ण मुरारी मोघे इंदौर के मेयर और खरगोन से सांसद रहे। ग्वालियर का सिंधिया परिवार भी मूलत: मराठी भाषी है जिसे हिंदी भाषी लोगों ने दिलों में जगह दी। कुशाभाऊ ठाकरे तो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के पितृपुरूष रहे, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मप्र में तुकोजीराव पवार का परिवार, छत्तीसगढ़ में रजनीताई उपासने, पंडरीराव कृदत्त, यशवंत राव मेधावाले, दिनकर डांगे विधायक रहे, उप्र में मधुकर दीघे जैसे अनेक नेता विधानसभा पहुंचे। गंभीर अध्ययन से अनेक ऐसे उदाहरण हर क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र ने हिंदी वासियों को दिल में जगह दी। अनेक सांसद, विधायक और मंत्री महाराष्ट्र की सरकार में रहे। इस तरह कभी हिंदी और मराठी विवाद सामने नहीं आया। आजादी के 75 सालों के बाद इस तरह का विवाद चिंतनीय है और सोचनीय भी। हिंदी साहित्य, पत्रकारिता, थियेटर, फिल्म और कलाएं महाराष्ट्र में फली-फूलीं। यह सहज संवाद और आत्मीयता समाज के स्तर पर भी थी, भाषा के स्तर पर भी। हिंदी देश के बड़े क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसका आदर करते हुए ही हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किंतु राज्यों

में राज्य की भाषाएं आदर पाएं और उच्चासन भी, इससे किसी को आपत्ति कहां है। क्या सरकारों और राजनेताओं की हिम्मत है कि वे अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर सकें? उन्हें पता है कि ऐसा करने से अभिभावकों का जो प्रतिरोध सामने आएगा, उसका वे सामना नहीं कर सकेंगें। इसलिए भाषा प्रेम की नौटंकी से बाज आकर ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिससे भारतीय भाषाओं का न्यूनतम सम्मान तो सुरक्षित रह सके। जाहिर है ऐसे विवाद अंग्रेजी की जड़ों को गहरा करने में सहायक बनेगें। इससे भारतीय भाषाएं उपेक्षा और अनादर की शिकार होती रहेंगी।

मातृभाषा में हो प्राथमिक शिक्षा

कई देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी अन्य भाषा में नहीं। मराठी भाषा में प्राथमिक शिक्षा दिए जाने की माँग कतई नाजायज नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए। किंतु 'हिंदी विरोध' को किसी नारे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके राजनीतिक इस्तेमाल से बचना सबसे बड़ी ज़रूरत है। मराठी को अध्ययन, अध्यापन की भाषा बनाने के लिए आंदोलन होना चाहिए पर वह हिंदी के तिरस्कार से नहीं होगा। मराठी को महाराष्ट्र में राजभाषा का दर्ज़ा मिला हुआ है, तो राज्य सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि उसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सारे जतन करे। राजनीति का यह द्वंद समझा जा सकता है कि वह अपने सारे क्रिया व्यापार एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी) में करती है और आम जनता के भावनात्मक शोषण के लिए स्थानीय भाषाओं के विकास की नारेबाजी करती है। महाराष्ट्र की फ़िजाओं में इस तरह की बातें फैलाना वास्तव में इस क्षेत्र की तासीर के ख़िलाफ़ है। भारतीय भाषाओं के बिना हम कितने बेचारे हो जाएँगे इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हजारों-हजार भाषाएं, हजारों-हजार बोलियाँ, हज़ारों शब्द लुप्त होने के कगार पर हैं और अँगरेज़ी का साम्राज्यवाद उन्हें निगलने के लिए खड़ा है, तो ऐसे समय में क्या हम ऐसी फ़िज़ूल की बहसों के लिए अपना वक्त खराब करते रहेंगे।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।)

उत्तराखंड में फिल्म निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक दिवसीय कार्यशाला

उत्तराखंड बनेगा फिल्म निर्माण का हबः बंशीधर तिवारी

उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला। बुधवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित होटल में यह कार्यशाला नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद (UFDC) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय 'उत्तराखंड में फिल्मिंग इकोसिस्टम के विकास' रखा गया।

कार्यशाला का शुभारंभ यूएफडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बंशीधर तिवारी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की फिल्म निदेशक सुश्री शिल्पा राव और एनएफडीसी के महाप्रबंधक श्री अजय धोके द्वारा दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया।

इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े प्रमुख निर्माता, नीतिगत विशेषज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र बिंदु राज्य में फिल्म निर्माण हेतु नीतिगत सुधार, अवसंरचना विकास और प्रतिभा संवर्धन रहा।

यूएफडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बंशीधर तिवारी ने कहा, 'माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को फ़िल्म निर्माण हब के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। यह कार्यशाला राज्य और केंद्र की नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' श्री बंशीधर तिवारी, महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UFDC ने कहा कि उत्तराखंड की फिल्म नीति क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी बनाई गई है। उन्होंने बताया, 'अब क्षेत्रीय सिनेमा को दी जाने वाली सब्सिडी 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ तक कर दी गई है। इस नीति के तहत अब तक 20 से 25 गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय फिल्में बन चुकी हैं।'

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के कम चर्चित स्थलों पर शूटिंग करने पर कुल फ़िल्म निर्माण लागत का 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है। साथ ही, उत्तराखंड में स्थानीय कलाकारों को काम देने वाले निर्माताओं को भी विशेष सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए 25 लाख की एकमुश्त सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में सिनेमा हॉल की संख्या बढ़ाना है। UFDC स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, कलाकारों, संसाधनों और

परिवहन सुविधाओं की एकीकृत सूची तैयार कर रहा है ताकि फिल्म निर्माताओं को राज्य में काम करने में आसानी हो।

उन्होंने बताया कि एनएफडीसी के सहयोग से राज्य का अपना फिल्म फेस्टिवल और उत्तराखंड राज्य फिल्म पुरस्कार शुरू करने पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। साथ ही, क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को ओटीटी मंचों तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती के WAVES OTT से समन्वय स्थापित किया जाएगा। श्री तिवारी ने यह भी बताया कि स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने राज्य में फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों- जैसे शूटिंग लोकेशन, उपकरण, कलाकार, लॉजिस्टिक्स आदि-को एकीकृत करने हेतु एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। 'हम सभी सुझावों के लिए खुले हैं और उत्तराखंड को एक फिल्म-निर्माता अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं,' उन्होंने जोड़ा।

सुश्री शिल्पा राव, निदेशक (फिल्म्स), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत को वैश्विक सिनेमा हब के रूप में विकसित करने की दिशा में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट, प्रतिभा और तकनीक को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसीलिए भारत सरकार ने वेव्स समिट किया। वेव्स बाज़ार डॉट कॉम पर फ़िल्म निर्माण से जुड़े लोग अपने लिए अवसर देख सकते हैं। इंडियन सिने हब का एकीकृत पोर्टल फ़िल्म निर्माताओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। उन्होंने यह भी कहा कि आज मोबाइल स्क्रीन पर व्यक्तिगत रूप से फिल्में देखने का चलन बढ़ा है, ऐसे में समुदाय स्तर पर सामूहिक फिल्म प्रदर्शन की संस्कृति को पुनर्जीवित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कम लागत वाले सिनेमा हॉल को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में समुदाय-आधारित फिल्म देखना बढ़े।

महाप्रबंधक एनएफडीसी अजय ढोके ने एनएफडीसी के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में इंडियन सिने हब के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली फ़िल्म सब्सिडी सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

यूएफडीसी के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने उत्तराखंड की नवाचारपूर्ण फिल्म नीति पर एक विशेष

'माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को फि़ल्म निर्माण हब के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। यह कार्यशाला राज्य और केंद्र की नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड की फिल्म नीति क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी बनाई गई है। अब क्षेत्रीय सिनेमा को दी जाने वाली सब्सिडी 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ तक कर दी गई है। इस नीति के तहत अब तक 20 से 25 गुणवत्तापूर्ण क्षेत्रीय फिल्में बन चुकी हैं। राज्य के कम चर्चित स्थलों पर शूटिंग करने पर कुल फि़ल्म निर्माण लागत का 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन सब्सिडी दी जाती है। साथ ही, उत्तराखंड में स्थानीय कलाकारों को काम देने वाले निर्माताओं को भी विशेष सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए 25 लाख की एकमुश्त सब्सिडी की व्यवस्था भी की गई है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में सिनेमा हॉल की संख्या बढ़ाना है। UFDC स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, कलाकारों, संसाधनों और परिवहन सुविधाओं की एकीकृत सूची तैयार कर रहा है ताकि फिल्म निर्माताओं को राज्य में काम करने में आसानी हो।

श्री बंशीधर तिवारी, आईएएस
महानिदेशक सूचना एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UFDC

प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने 'प्रतिभा, प्रशिक्षण और तकनीक' को उत्तराखंड के फिल्म निर्माण मॉडल के तीन आधार स्तंभ बताते हुए कहा, 'हम केवल बाहरी निर्माताओं को ही नहीं, बल्कि स्थानीय कहानीकारों और तकनीशियनों को भी मंच देना चाहते हैं जिससे क्षेत्रीय सिनेमा को नई ऊर्जा मिले।'

डॉ. उपाध्याय ने नीति के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं जैसे उत्पादन सब्सिडी, लोकेशन पर सहयोग, फिल्म संस्थानों की स्थापना, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा स्क्रीन के निर्माण, तथा वन एवं सार्वजनिक स्थलों पर फिल्मांकन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की भी जानकारी साझा की।

इंडिया सिने हब के सहायक वाईस प्रेसिडेंट श्री राम कुमार विजयन ने 'इंडियन सिने हब' पोर्टल की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मंच राज्य सरकारों, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय नोडल अधिकारियों से अनुमतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को एकीकृत और सरल बनाता है। उन्होंने पोर्टल पर उपलब्ध समग्र संसाधन निर्देशिका की भी जानकारी दी।

कार्यशाला के समापन पर आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागी फिल्म निर्माताओं और फि़ल्म निर्माण से जुड़े अन्य लोगों की विभिन्न नीतिगत जिज्ञासाओं का समाधान एनएफडीसी और यूएफडीसी के अधिकारियों द्वारा किया गया।

इससे पूर्व, NFDC और UFDC के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें राज्य को एक सशक्त फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने, सिनेमा हॉल अवसंरचना को विस्तार देने, क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन देने और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु अनुकूल नीतिगत पहलों पर विस्तृत विमर्श किया गया। बैठक में फि़ल्म निर्माण, क्षेत्रीय सिनेमा, स्क्रीन की उपलब्धता और प्रोत्साहन योजनाओं जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा हुई।

इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी जिनमें प्रमुख रूप से सुश्री शिल्पा राव (निदेशक फिल्म्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), श्री अजय धोके (महाप्रबंधक, एनएफडीसी), श्री आशीष त्रिपाठी अपर निदेशक सूचना सुश्री श्रुति राजकुमार (उपाध्यक्ष एवं प्रमुख, इंडिया सिने हब), श्री मयूर पटेल (प्रबंधक, फिल्म बाजार, एनएफडीसी), श्री नचिकेत शिरोलकर (सलाहकार, अंतरराष्ट्रीय प्रचार एवं फिल्म महोत्सव, एनएफडीसी), श्री अभय कुमार (प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनीकॉप्स) उपस्थित रहे।

पहले रुका, अब फिर बजा पंचायत का चुनावी बिगुल

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई डेट घोषित

24 और 28 जुलाई को वोटिंग, 31 जुलाई को काउंटिंग

किरण कांत शर्मा
स्टेट हैड
ई.टी.वी. भारत

उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तराखंड शासन की ओर से चुनावी कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 30 जून को जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के तहत मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण के तहत मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा। साथ ही 31 जुलाई को एक साथ मतगणना होगी।

पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान:
अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के नए चुनावी कार्यक्रम को जारी कर दिया है। पहली अधिसूचना 21 जून को जारी की गई थी लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। हालांकि, अब रास्ता साफ होने के बाद नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत 89 विकासखंडों और 7499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे।

प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होने हैं। इसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पदों, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499 पदों, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 पदों और सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के कुल 66,418 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8,276 मतदान केंद्र जबकि 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।

47 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट:
प्रदेश के 12 जिलों में मतदाताओं की संख्या 4,777,072 है। इसमें 2,465,702 पुरुष मतदाता और 2,310,996 महिला मतदाता के साथ ही 374 अन्य मतदाता शमिल हैं। साल 2019 के मुकाबले साल 2025 में मतदाताओं की संख्या में करीब 10.57 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। यानी कुल 456,793 मतदाता बढ़े हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पोस्ट के अनुसार मतपत्रों का रंग भी तय किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग का मतपत्र, प्रधान के लिए हरा रंग का मतपत्र होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला रंग का मतपत्र होगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

95 हजार से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी संपन्न कराएंगे पंचायत चुनाव:
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मतदान और मतगणना के लिए कुल 95,909 अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके तहत मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारियों के रूप में 11,849 कर्मचारियों, मतदान स्थल पर मतदान अधिकारियों के रूप में 47,910 कर्मचारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट/ जोनल मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी/ प्रभारी अधिकारियों के रूप में 450 अधिकारियों और मतदान स्थलों पर 35,700 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए कुल 5,620 वाहन लगाए जाएंगे। इसमें 3,342 हल्के वाहन और 2,278 भारी वाहन शामिल हैं। पंचायत चुनाव में 55 सामान्य प्रेक्षकों और 12 आरक्षित प्रेक्षकों की तैनाती की जाएगी यानी कुल 67 प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे।

निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विशेष तैयारी:
मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को

कुमाऊं	पहला चरण- 24 जुलाई	दूसरा चरण- 28 जुलाई
अल्मोड़ा	ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत, भैंसियाछाना, लमगड़ा, चौखुटिया	सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग, द्वाराहाट
बागेश्वर	बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट	....
उधम सिंह नगर	खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर	रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर
पिथौरागढ़	लोहाघाट, पाटी, धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी, कनालीछीना	विण, मूनाकोट, बेरीनाग, गंगोलीहाट
नैनीताल	रामगढ़, बेतालघाट, धारी, ओखलकांडा	हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, कोटाबाग
चंपावत	....	चंपावत, बाराकोट

गढ़वाल	पहला चरण- 24 जुलाई	दूसरा चरण- 28 जुलाई
उत्तरकाशी	मोरी, पुरोला और नौगांव	डुंडा, चिन्यालीसौड़, भटवाड़ी
चमोली	देवाल, थराली, ज्योर्तिमठ और नारायणबगड़	पोखरी, दशोली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण
टिहरी गढ़वाल	जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार और भिलंगना	कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर. चंबा
देहरादून	चकराता, कालसी और विकासनगर	डोईवाला, रायपुर, सहसपुर
पौड़ी गढ़वाल	खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडांडा, बीरौंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर और पोखड़ा	यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट, कल्जीखाल
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि	....
हरिद्वार	अभी चुनाव नहीं	

पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से किए जाने को लेकर मतदान एवं मतगणना कर्मियों की तैनाती सॉफ्टवेयर के जरिए रेंडमाइजेशन प्रणाली से की जाएगी। चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी या मादक पदार्थ जैसी वस्तुओं पर लगाम लगाने के लिए जिला स्तर पर तीन टीमें गठित की जाएंगी। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीमें साथ काम करेंगी। हर जिले में एक प्रभारी अधिकारी (व्यय) होगा, जो रोजाना जनपद में की गई जब्ती की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के जरिए आयोग को भेजेगा।

पहले चरण में इन ब्लॉकों में होगा चुनाव:

24 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण होगा। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल के मिलाकर 49 ब्लॉकों में चुनाव होंगे। कुमाऊं के 23 जबकि गढ़वाल के 26 विकासखंडों में वोटिंग होगी।

वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 28 जुलाई को उत्तराखंड के 40 ब्लॉकों में चुनाव होगा। इसमें कुमाऊं के 18 जबकि गढ़वाल के 22 विकासखंडों में वोटिंग होगी।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चुनावी कार्यक्रम:

28 जून को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब पहले चरण के चुनाव के लिए 2 जुलाई से 5 जुलाई 2025 तक सुबह 8 बजे से नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। 14 जुलाई को पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। वहीं, दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को है। उसके लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा।

31 जुलाई को होगी मतगणना:

दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 31 जुलाई को होगी। उसी दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आ जाएगा।

(ई.टी.वी. भारत में प्रकाशित खबर के अनुसार)

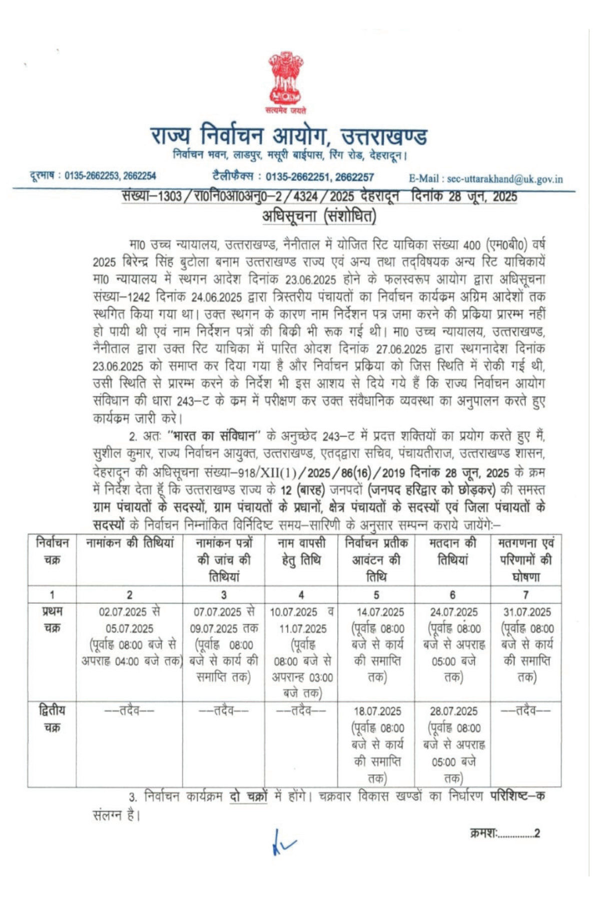

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या–1303/रा0नि0आ0अनु0–2/4324/2025 देहरादून दिनांक 28 जून, 2025

अधिसूचना (संशोधित)

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 400 (एम0बी0) वर्ष 2025 बिरेन्द्र सिंह बुटोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा तद्विषयक अन्य रिट याचिकायें मा0 न्यायालय में स्थगन आदेश दिनांक 23.06.2025 होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या–1242 दिनांक 24.06.2025 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कार्यक्रम अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था। उक्त स्थगन के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पायी थी एवं नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री भी रूक गई थी। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित ओदश दिनांक 27.06.2025 द्वारा स्थगनादेश दिनांक 23.06.2025 को समाप्त कर दिया गया है और निर्वाचन प्रक्रिया को जिस स्थिति में रोकी गई थी, उसी स्थिति से प्रारम्भ करने के निर्देश भी इस आशय से दिये गये हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान की धारा 243–ट के क्रम में परीक्षण कर उक्त संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम जारी करे।

2. अतः **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 243–ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या–918/XII(1)/2025/86(16)/2019 **दिनांक 28 जून, 2025** के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के **12 (बारह)** जनपदों **(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)** की समस्त **ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों** के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे:–

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चक्र	02.07.2025 से 05.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	07.07.2025 से 09.07.2025 तक (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	10.07.2025 व 11.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक)	14.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	31.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)
द्वितीय चक्र	––तदैव––	––तदैव––	––तदैव––	18.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	28.07.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	––तदैव––

3. निर्वाचन कार्यक्रम दो चक्रों में होंगे। चक्रवार विकास खण्डों का निर्धारण **परिशिष्ट–क** संलग्न है।

क्रमशः..............2

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयुष विभाग नया इतिहास लिख रहा है: दीपेंद्र चौधरी

सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपेंद्र चौधरी जी से विशेष बातचीत

उत्तराखण्ड सचिवालय के गलियारों में यदि किसी अधिकारी का नाम सादगी, संकल्प और संवेदना के प्रतीक रूप में लिया जाता है, तो वह हैं दीपेन्द्र चौधरी। प्रचार से दूर, परिणामों में विश्वास रखने वाले इस अधिकारी ने अपने अनुशासित और सौम्य व्यक्तित्व से शासन प्रशासन की कार्यशैली को न केवल नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि हर जिम्मेदारी को समाजहित की कसौटी पर खरा भी उतारा। श्री चौधरी की कार्यशैली की सबसे खास बात यह है कि वे कभी किसी 'मंच' या 'माइक' पर नहीं दिखते, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके फैसलों की गूंज सुनी जाती है। वे उन अधिकारियों में हैं जो 'फाइल से पहले फील्ड' की भावना में विश्वास करते हैं। दीपेन्द्र चौधरी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। पिता पूर्व सैनिक रहे और मां एक कर्मठ गृहिणी। पांच बहनों के बाद परिवार में जन्मे इकलौते पुत्र ने बचपन से ही सादगी, स्वावलंबन और आत्म-सम्मान को जीवन की प्राथमिक शिक्षा बना लिया। शिक्षा की नींव सरस्वती शिशु मंदिर से पड़ी, तो आत्मानुशासन की गूंज सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में मिली। यहां से उन्होंने वह दृष्टि और ऊर्जा प्राप्त की, जिसने उन्हें जीवन की हर परीक्षा में आगे बढ़ना सिखाया। नैनीताल से विज्ञान विषय में स्नातक और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही यह संकल्प था कि समाज की सेवा करनी है और इस सेवा का सबसे प्रभावशाली रास्ता प्रशासनिक सेवा ही है। यही सोच उन्हें सिविल सेवा की ओर ले गई। दीपेन्द्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के अनेक जिलों में कार्य करते हुए समाज की जटिल समस्याओं को सीधे सुलझाया। चाहे शहरों की यातायात व्यवस्था हो या गांवों के विद्यालय, पहाड़ की वनाधिकार संबंधी उलझनें हों या खनन व आबकारी जैसे संवेदनशील विभाग-हर जिम्मेदारी में उन्होंने मानवमूल्यों को प्राथमिकता दी। वे जब भी किसी जिले में तैनात रहे, वहां की सबसे बड़ी ताकत बन गए-'जनता की आवाज़'। पेश है वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक विश्लेषक हरिशंकर सैनी से हुई उनकी बातचीत के कुछ अंश.. संपादक

उत्तराखंड में आयुष विभाग की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों और औषधीय वनस्पतियों से भरपूर है। आयुष क्षेत्र में हम बड़ी तेजी से विकास कर रहे हैं। राज्य में 770 आयुर्वेदिक राजकीय चिकित्सा अधिकारी, 117 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, चार यूनानी चिकित्सा अधिकारी वूमेन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सालय एवं डिस्पेंसिटी में दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं साथ ही नेशनल आयुष मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, आर.एस.बी.के., आर.सी.एच. प्रोग्राम आदि के अंतर्गत भी 300 से अधिक चिकित्सक अपनी सेवाएंदे रहे हैं। राज्य के हर जिले में आयुष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक अंब्रेला सिस्टम के अंतर्गत हर चिकित्सालय में एक आयुष बिजली स्थापित की गई है। आयुष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मजबूत नेतृत्व में आयुष विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में नई दिशा और गति पाई है।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में आयुष विभाग ने कौन-कौन से नए आयाम स्थापित किए हैं?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुष को राज्य की प्राथमिकता दी है। उन्होंने विभाग को हर स्तर पर सशक्त बनाने का काम किया है। आयुष को केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि संपूर्ण विकास के उपकरण के रूप में लिया जा रहा है। 'आयुष ग्राम' योजना, वेलनेस टूरिज्म, औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती, और आयुष आधारित स्वरोजगार एवं उद्योगों को बढ़ावा इसी का हिस्सा हैं। धामी जी का लक्ष्य है कि उत्तराखंड देश में 'आयुष प्रदेश' के रूप में पहचाना जाए।

'आयुष प्रदेश' बनाने की अवधारणा पर विस्तार से बताएं।

'आयुष प्रदेश' का मतलब है कि आयुष पद्धतियां जन-जन तक पहुंचें और राज्य के विकास का हिस्सा बनें। इसका मतलब है आयुष शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और पर्यटन में आयुष को जोड़ना। हमने 'आयुष ग्राम' की योजना शुरू की है, जहां पंचकर्म एवं वैलनेसकेंद्र, योग केंद्र, जड़ी-बूटी की खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं आयुष प्रोडक्ट वैल्यू

एडिशन और आयुष आधारित प्राकृतिक जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाता है। मुख्यमंत्री धामी की पहल से इन योजनाओं को तेज गति मिली है।

आयुष शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं?

राज्य में मैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है , क्योंकि यूजीसी से अनुमोदित है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से सम्बद्ध है। वर्तमान में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पास हेरिटेज दो कॉलेज ऋषिकुल केंपस जिसको हरिद्वार में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1919 में स्थापित किया था एवं दूसरा हेरिटेज कैंपस गुरुकुल केंपस जिसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1921 में हरिद्वार में स्थापित किया था, इसके अतिरिक्त मुख्य परिषद में 2014 में हर्रावाला में सरकारी कैंपस स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय के पास 16 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसमें पतंजलि जैसे ख्याति प्राप्त कॉलेज भी हैं। एक यूनानी प्राइवेट कॉलेज एक होम्योपैथी प्राइवेट कॉलेज संचालित है तथा मुख्य परिसर में एक होमियोपैथिक सरकारी कॉलेज की स्थापना की जा रही है। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल परिसर को भारत सरकार की अपग्रेडेशन स्कीम के तहत अभी 178 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है जिसको बहुत शिक्षा से विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ऑल इंडिया इंस्टीटयूट आफ आयुर्वेद स्टार का कैंपस बनाया जाएगा। प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश में आयुष कॉलेजों की क्रमशः संख्या बढ़ाई गई है और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। हम छात्रों को शुद्ध आयुष प्रैक्टिस, शोध, स्टार्टअप, और उद्यमिता रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आयुष शिक्षा को व्यावसायिक और रोजगार उन्मुख बनाना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी के समर्थन से हमने स्कॉलरशिप, रिसर्च ग्रांट, और उद्योग से जुड़ाव, इंडस्ट्री व शैक्षिक संस्थान, सरकारी संस्थाओं, शोध संस्थान के मध्य एम0ओ0यू0 को बढ़ावा दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष का महत्व कैसे बढ़ाया जा रहा है?

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, इसलिए आयुष यहां बहुत उपयोगी है। पूरे प्रदेश भर के दूरस्थ दुर्गम इलाकों में भी आयुष के चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। नेशनल आयुष मिथुन के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से आयुष आरोग्य मंदिर कम कर रहे हैं जहां पर स्थानीय लोगों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ प्रबंधन के लिए योग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है एवं जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम इत्यादि किये जाते हैं। हमने स्थानीय युवाओं को आयुष आधारित स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया है। औषधीय पौधों की खेती, घरेलू उपचार, और आयुष पॉलिसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव एवं छूट का प्रावधान किया है विभिन्न योजनाएं भी आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इन पहलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है।

आयुष और एलोपैथी के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे?

आयुष और एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा के वैध तरीके हैं। हम इन्हें एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखते हैं। इसी को जिला जिला अस्पताल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आयुष बैंक की स्थापना भी उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है जिससे सभी केदो पर सभी पद्धतियों की चिकित्सा परामर्श लोगों को प्राप्त हो। हमारा प्रयास है कि दोनों पद्धतियों को एकीकृत कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। मुख्यमंत्री धामी ने भी इस समेकित दृष्टिकोण को अपनाने में पूरी मदद की है।

आयुष और पर्यटन का मेल उत्तराखंड के लिए क्या अवसर लाता है?

उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध योग और ध्यान केंद्र है। यहां विश्व प्रसिद्ध बाबा योग गुरु रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा स्थापित पतंजलि योग केंद्र हरिद्वार में स्थित है। ऋषिकेश में प्राचीनतम शिवानंदयोग केंद्र, कई अन्य प्राचीन सिद्ध स्थान एवं योग केंद्र ऋषिकेश सहित उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित है। अब हम वेलनेस, पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा, वैलनेस- टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यटक आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म, और योग थेरेपी का लाभ उठा रहे हैं। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री धामी के दूरदर्शी फैसलों से यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है।

प्रश्न 08: उत्तराखंड के युवाओं को आयुष से कैसे जोड़ा जा रहा है?

उत्तर: हमारा ध्यान युवाओं को आयुष क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा और स्टार्टअप के अवसर देने पर है। सभी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेज के आयुर्वैदिक, होम्योपैथिक, यूनानी डॉक्टर के स्किल डेवलपमेंट के लिए फार्मेसी एवं उद्योगों का प्रशिक्षण के लिए कहां जा रहा है। जिससे चिकित्सा के साथ-साथ फार्मा उद्योग को भी समझ सके। आयुर्वेद में

आयुष विभाग की महत्वपूर्ण उलपब्धियां

उत्तराखंड, अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत के लिए पहचाना जाने वाला राज्य, आज आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के क्षेत्र में भी एक नई पहचान गढ़ रहा है। इस बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री दीपेंद्र चौधरी, जो वर्तमान में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन के सचिव हैं। उनके कुशल प्रशासनिक नेतृत्व और नवाचार-प्रधान दृष्टिकोण ने आयुष को महज़ एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यटन और आयुष शिक्षा का वाहक बना दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप, सचिव दीपेंद्र चौधरी की टीम अभी हाल में ही उत्तराखंड आयुष पॉलिसी 2024 को लागू किया है जिसमें उत्तराखंड में आयुष उद्योगों मैं इन्वेस्टमेंट के लिए विशेष पॉलिसी रियायत एवं स्कीम तथा छठ का प्रावधान दिया गया है जो पूरे भारत में विशिष्ट स्थान रखती है। हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने देश की पहली अपने प्रकार की विशिष्ट योग पॉलिसी का माननीय पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में अभी इसी महीने में अनुमोदन किया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 'आयुष ग्राम', वेलनेस टूरिज्म, औषधीय पादपो एवं सौगंध पौधों की खेती, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, और समेकित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाओं को ज़मीनी हकीकत बना रही है। उत्तराखंड के एसएससी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड को को 'आयुष प्रदेश' के रूप में विकसित करने की दिशा में आयुष विभाग द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, वे न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकते हैं।

एमडीएमएस में शोधार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है एवं पीएचडी के पाठ्यक्रम आयुर्वेद एवं इंट्रडिसीप्लिनरी साइंस में भी किए गए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न सेक्टर में पीजी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किया जा रहे हैं। यह करने के का उद्देश्य है कि युवा सिर्फ डॉक्टर न बनें, बल्कि आयुष में उद्यमी भी बनें- जैसे हर्बल उत्पाद, कॉस्मेटिकउत्पाद, आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियां निर्माण, फार्मेसी, वेलनेस क्लीनिक, पंचकर्म सेंटर और योग रिसॉर्ट की स्थापना आदि। इससे न केवल उनका करियर संवरता है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है।

अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं?

हमने आयुष आधारित अनुसंधान को वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में ठोस पहल की है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा एमडीएमएस एवं पीएचडी को लेकर लगभग 150 से ज्यादा शोध कार्य प्रतिवर्ष किए जाते हैं। जिनका विभिन्न रिसर्च इंटरनेशनल जनरल में प्रकाशन, बुक राइटिंग भी समय-समय पर होता है। नॉलेज शेयरिंग के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद होम्योपैथी निदेशालय द्वारा समय-समय पर आर.ओ.टी.पी., सी.एम.ई, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंशन, वर्कशाप एवं सेमिनार आदि आयोजित किया जा रहे हैं। विभिन्न जन हित से जुड़े हुए कैंपेन, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान आदि में भी आयुष विभाग चकराता से प्रतिभाग कर रहा है। उत्तराखंड की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, लोक उपचार और जड़ी-बूटियों पर आधारित एविडेंस-बेस्ड स्टडीज करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही हम विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और रिसर्च संस्थानों के साथ MoU कर रहे हैं, ताकि आयुष की प्रभावशीलता पर वैज्ञानिक प्रमाण मिले और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले। उत्तराखंड में अभी हाल में ही वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया जिसमें विश्व का रिकॉर्ड बना जिसमें 10000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। 350 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो मेभाग लिया। कुछ समय पहले ही देश के एसएससी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इन्वेस्टर सबमिट में आकर देश भर के उद्योगपतियों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। उनके निर्देशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड आयुष नीति को विशेष रूप से डिजाइन किया गया जिसमें उद्योगपतियों को आयुष उद्योग संचालित करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

महिलाओं की भागीदारी को आयुष के माध्यम से कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है?

महिलाओं के लिए आयुष क्षेत्र में विशेष अवसर हैं। हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वरोजगार समूहों को जड़ी-बूटी प्रसंस्करण, हर्बल उत्पाद निर्माण ट्रेनिंग देने की योजना और जन स्वास्थ्य के लिए घर-घर में एक किचन के अंतर्गत औषधीय क्या कैसे प्रयोग करना है घरेलू एवं पारंपरिक जड़ी बूटियां एवं किचन मसाले पर आधारित स्तर पर उसके लिए भी अभियान चलाने की योजना है, जिससे प्राथमिक स्तर पर छोटी परेशानियों के लिए घर पर ही निवारण करने में मदद मिले। आयुष नीति में हम आयुष उद्योगों के लिए महिलाओं को वारीयता प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है, और आयुष इसमें एक सक्षम माध्यम बनकर उभर रहा है।

उत्तराखंड को 'ग्लोबल वेलनेस डेस्टिनेशन' बनाने के प्रयासों पर कुछ प्रकाश डालिए।

उत्तराखंड की प्रकृति, शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही देश-दुनिया को आकर्षित करती रही है। अब हमारा प्रयास है कि इसे ग्लोबल वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए हर्बल ट्रेल, योग ग्राम, पंचकर्म रिट्रीट, और अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव जैसे आयोजनों की योजना बनाई गई है। हम राज्य के पर्यटन स्थलों को वेलनेस टूरिज्म से जोड़ रहे हैं ताकि आयुष आधारित स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर आपकी क्या नीति है?

आयुष क्षेत्र में निजी निवेश का स्वागत है। हमने (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट प्रस्तावित करने की योजना है हैं। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि गुणवत्ता और नवाचार को भी बल मिलेगा। औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग यूनिट, आयुर्वेदिक उत्पाद निर्माण और वेलनेस सेंटर जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आप आयुष के भविष्य को कैसे देखते हैं?

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आयुष न केवल भारत की ताकत बनेगा, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में एक अहम भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड इसके केंद्र में रहेगा- एक ऐसा राज्य जो अपने प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक मूल्यों और कुशल प्रशासन के बल पर 'आयुष प्रदेश' के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का जो विज़न है, वह हमारे लिए पथप्रदर्शक है, और हम पूरी निष्ठा से उस दिशा में कार्यरत है

भविष्य की योजनाएं और लक्ष्य क्या हैं?

हमारा सपना है कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देश के अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो। के लिए तथा आवश्यक शैक्षणिक पदों की भर्ती एमएसआर के अनुसार फर्नीचर उपकरण एवं संसाधनों की प्रतिपूर्ति, एवं उन आवश्यकताओं के लिए फेस वाइस मैनर में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। ऋषिकुल में 178 करोड़ की विकास की परियोजना एवं हर्रावाला के विश्वविद्यालय परिसर में होम्योपैथिक कॉलेज एवं भारतीय चिकित्सा परिषद के भवन का का निर्माण गतिमान है। राज्य में 416 जीएमपी सर्टिफाइड आयुर्वैदिक फार्मेसी कार्यरत है। जिसमें कुछ व्हो जीएमपी सिस्टम आधारित आयुष्मान प्रीमियम एवं स्टैंडर्ड मार्क सर्टिफाइड है। राज्य में अपनी स्टेट औषधि निर्माण शाला है हरिद्वार में। तथा विदेश में ड्रग एनफोर्समेंट का एक सशक्त सिस्टम लाइसेंसिंग अधिकारी के माध्यम से स्थापित है तथा राज्य की अपनी राजकीय औषधि प्रयोगशाला अभी हरिद्वार में स्थापित है। सात प्राइवेट ड्रग टेस्टिंग लैब राज्य द्वारा अनुमोदित हैं दिन में टेस्टिंग एवं रिसर्च की सुविधा स्थापित हैं जिनका एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण भी किया गया है। हर जिले में आयुष वेलनेस क्लस्टर भी स्थापित करने योजना है, हर्बल मंडी, हर्बल जन औषधि केंद्र आदि स्थापित करने के लिए भी विभाग प्रयासरत है। आयुष के जरिए ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में हम इस लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा करेंगे।

उत्तराखंड में आयुष विभाग के बदलाव और विकास के पीछे सचिव दीपेंद्र चौधरी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सक्रिय नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके प्रयास न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार ला रहे हैं, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी एक नया अध्याय लिख रहे है

संविधान की प्रस्तावना पर छिड़ी बहस

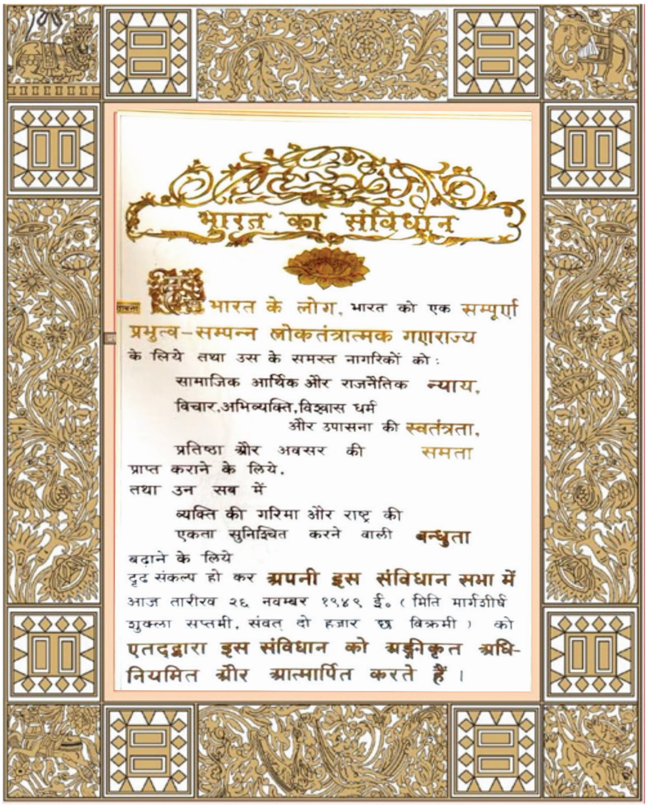

भारत का संविधान

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को :

सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये
दृढ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छ विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान की मूल प्रस्तावना

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारिख २६ नवंबर, १९४९ ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित करते हैं।

42वें संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना

अजय कुमार,
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय राजनीति में जब भी संविधान को लेकर कोई सवाल उठता है, तब वह बहस सिर्फ कानून की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह देश की आत्मा और उसकी पहचान से जुड़ जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जो बयान दिया, उसने न केवल संविधान की प्रस्तावना बल्कि स्वतंत्र भारत की विचारधारा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे, वे शब्द उस दौर की तानाशाही में बिना जनता की सहमति के थोपे गए थे और अब समय आ गया है कि इन शब्दों को हटाने पर गंभीर विचार किया जाए। उनका यह बयान प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक वैचारिक लड़ाई की ओर संकेत करता है जो अब साफ तौर पर राष्ट्र की पहचान पर केंद्रित हो गई है। जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचल दिया गया था। प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई थी, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था और संसद मात्र एक औपचारिकता बन कर रह गई थी। ऐसे समय में जब नागरिकों की आवाज़ को दबा दिया गया था, तब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे। यही वह आधार है जिस पर संघ का कहना है कि यह बदलाव लोकतंत्र के विरुद्ध था और इसीलिए अब इन्हें हटाने की आवश्यकता है।

दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि संघ 1949 से ही संविधान का विरोध करता आ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संघ समर्थकों ने पंडित नेहरू और डॉ. भीमराव आंबेडकर के पुतले तक जलाए थे। वहीं कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने इसे संघ की 'मनुस्मृति आधारित भारत' की सोच का हिस्सा बताया और कहा कि यह प्रयास दरअसल भारत के बहुलतावादी और समावेशी स्वरूप को मिटाने की दिशा में एक कदम है। लेकिन इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में देखना एक सीमित दृष्टिकोण होगा क्योंकि यह बहस आज की नहीं है, इसका इतिहास उस समय से है जब संविधान सभा में ही इन शब्दों को लेकर मतभेद थे। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर केटी शाह ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों

को प्रस्तावना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। उनका मानना था कि इन शब्दों से संविधान की दिशा और नीति स्पष्ट होगी। लेकिन डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इन शब्दों को संविधान में जोड़ना लोकतंत्र के लचीलेपन को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने तर्क दिया था कि समाजवाद जैसे शब्द किसी एक आर्थिक विचारधारा को बाध्यकारी बना देंगे जबकि लोकतंत्र में नीति तय करने का अधिकार जनता और समय के अनुसार सरकारों के पास होना चाहिए।

डॉ. आंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया था कि समाजवादी मूल्यों की झलक संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही मौजूद है और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी मौलिक अधिकारों के माध्यम से दी गई है। इसलिए इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ना अनावश्यक है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने भी इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने की कभी सिफारिश नहीं की थी। उनका मानना था कि भारतीय संविधान का ढांचा ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी है और यह बिना कहे ही सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। लेकिन 1976 में जब देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ दिया। उस समय संसद में विपक्ष लगभग नगण्य था, जन प्रतिनिधित्व निष्क्रिय था और विरोध की आवाज़ें दबा दी गई थीं। सरकार ने इसे 'कल्याणकारी राज्य' की प्रतिबद्धता बताया लेकिन विपक्ष और अनेक संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बताया।

हालांकि इमरजेंसी के बाद 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई, तब वह चाहे तो इन शब्दों को प्रस्तावना से हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह भी इस बहस का एक दिलचस्प पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और कहा कि संविधान संशोधन तो संभव है लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वहीं 2024 में बलराम सिंह बनाम भारत सरकार केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है जो समय के साथ बदल सकता है और संसद को संशोधन का अधिकार है बशर्ते वह मूल संरचना को क्षति न पहुंचाए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में निहित है और राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करेगा।

लेकिन वैचारिक तौर पर यह बहस अभी समाप्त नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक स्रोत संघ के अनेक नेताओं का मानना है कि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारत की बहुसंख्यक परंपरा को नकारता है और इसके जरिए तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला है। वहीं समाजवाद के नाम पर सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस राज और निजी उद्यमिता के दमन का इतिहास भी याद दिलाया जाता है। दूसरी ओर, कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि ये शब्द संविधान के आदर्शों की व्याख्या करते हैं और भारत की विविधता को संरक्षण देते हैं। उनका मानना है कि यदि इन शब्दों को हटाया गया तो संविधान की आत्मा को गहरी चोट पहुंचेगी और यह देश को विभाजित करने वाली सोच की ओर ले जाएगा।

इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को लेकर चल रही बहस केवल दो शब्दों की नहीं, बल्कि देश की वैचारिक दिशा की है। यह बहस तय करेगी कि भारत की पहचान आने वाले वर्षों में कैसी होगी क्या हम विविधता में एकता को बनाए रखेंगे या किसी एकरूपता की ओर बढ़ेंगे? यह बहस इस बात को भी स्पष्ट करेगी कि क्या संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है या फिर वह पत्थर की लकीर है। यह बहस केवल नेताओं और अदालतों की नहीं, बल्कि देश की जनता की है। यह फैसला भारत के नागरिकों को करना है कि वे किस प्रकार का भारत चाहते हैं एक ऐसा भारत जो सबको साथ लेकर चले या एक ऐसा भारत जो एक सोच, एक दिशा और एक रंग में ढला हो। इसलिए यह जरूरी है कि इस बहस को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि संवैधानिक और नैतिक आधार पर देखा जाए ताकि हमारा लोकतंत्र और संविधान पहले से ज्यादा सशक्त और प्रासंगिक बन सके।

सीएम धामी पहुंचे एम्स ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हाल-चाल जाना

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स, ऋषिकेश पहुंचकर जनपद रुद्रप्रयाग में हुई बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का समुचित और त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने घायलों एवं उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना में घायलों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर एयर एंबुलेंस के माध्यम से एम्स लाया गया था। जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

नशीली दवाओं के खिलाफ महत्वाकांक्षी युद्ध का आहवान

नशीली दवाओं के के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस- 26 जून, 2025

ललित गर्ग

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीली दवाओं मुक्त दुनिया को निर्मित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने, कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गलत सूचनाओं का मुकाबला करना और नशीली दवाओं के बारे में तथ्यों को साझा करना है। साथ ही साक्ष्य आधारित रोकथाम, स्वास्थ्य जोखिमों और विश्व नशीली दवाओं की समस्या, उपचार और देखभाल से निपटने के लिए उपलब्ध समाधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अवैध ड्रग्स एवं तस्करी मानव के लिए बहुत बड़ी पीड़ा एवं संकट का स्रोत हैं। सबसे कमज़ोर लोग, खास तौर पर युवा लोग, इस संकट का खामियाजा भुगतते हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले और नशे की लत से जूझ रहे लोग अंधेरी दुनिया में भटकते हुए कई चुनौतियों का सामना कर रहे है। नशीली दवाओं एवं ड्रग्स के खुद के हानिकारक प्रभाव, उनके द्वारा झेला जाने वाला कलंक, स्वास्थ्य संकट और भेदभाव और अक्सर उनकी स्थिति के प्रति कठोर और अप्रभावी प्रतिक्रियाएं दुनिया को एक महासंकट में धकेल रही है। इसलिये नशे एवं नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन एवं तस्करी को रोकने के लिये दुनिया को एकजुट होकर इस महत्वाकांक्षी युद्ध को सफल बनाना नितांत अपेक्षित है।

हर साल संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) वैश्विक जागरूकता अभियानों और नीति सिफारिशों का मार्गदर्शन करने के लिए एक थीम निर्धारित करता है। 2025 की थीम है- ''जंजीरों को तोड़ना: सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति!'' यह नारा सामुदायिक समर्थन, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से निपटने में वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर देता है। यूएनओडीसी की विश्व

मादक पदार्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार, वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर 269 मिलियन लोगों ने मादक पदार्थों का उपयोग किया, जो वर्ष 2009 की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है तथा अनुमान है कि 35 मिलियन लोग मादक पदार्थ उपयोग विकारों से पीड़ित हैं। यह दिवस न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वैकल्पिक आजीविका सहित रोकथाम में निवेश का आहवान करता है- जो टिकाऊ लचीलेपन के निर्माण के साथ उन्नत एवं स्वस्थ मानव जीवन का आधार हैं। दुनिया में सभी राष्ट्रों में राजनीति और ड्रग्स का चोली दामन का संबंध है, सभी देशों में बड़ी राजनीतिज्ञ पार्टियों की नशा माफिया एवं नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ काफी मिलीभगत है और यही वजह है कि दुनिया 'नशीले पदार्थों की राजनीति' के युग से गुजर रही है। इसलिये भी यह समस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही है। जिससे समय के साथ दुनिया में हेरोइन, अफीम, गांजा, चरस के अलावा अन्य नशों के साथ कैप्सूल और नशीली दवाइयों का चलन बढ़ने लगा है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे लाखों व्यक्ति, परिवार और समाज प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिये यह दिवस एक स्वस्थ और नशीली दवाओं से मुक्त समाज बनाने के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियों, सामुदायिक सहभागिता और नुकसान कम करने की रणनीतियों के महत्व पर प्रकाश डालता है। पिछले वर्ष विश्वभर में 15-64 वर्ष की आयु के 300 मिलियन से अधिक लोगों ने नशीले पदार्थों का उपयोग किया है। मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार से पीड़ित 8 में से 1 व्यक्ति को उपचार मिल पाता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है। वैश्विक नशीली दवाओं का व्यापार प्रतिवर्ष 400 बिलियन डॉलर से अधिक उत्पन्न करता है, जिससे संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इस बड़े संकट की रोकथाम की आवश्यकता को महसूस करते हुए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर, 1987 को संकल्प 42/112 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इस दिवस को स्थापित किया। इसका लक्ष्य नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं से निपटने में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और दंडात्मक उपायों के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य-आधारित प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग शरीर में लगभग हर प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे गंभीर अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम सामने आते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन से दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियाँ पैदा होती हैं, जिसमें ओपिओइड, मेथ और सिंथेटिक ड्रग्स सबसे ज्यादा मृत्यु दर और दीर्घकालिक अंग क्षति का कारण बनते हैं। इसके अलावा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मानसिक स्वास्थ्य परिणाम उपयोगकर्ता से परे तक फैल जाते हैं, जिससे अक्सर परिवार टूट जाते हैं, रोजगार छिन जाता है और अपराध दर बढ़ जाती है।

भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक

बढ़ता हुआ संकट है, जो भौगोलिक रूप से कमजोर, बढ़ती उपलब्धता और कम उम्र में इसकी शुरुआत से प्रेरित है। यह समस्या सभी आयु समूहों में फैली हुई है, लेकिन युवाओं में यह विशेष रूप से चिंताजनक है, जिसके स्वास्थ्य और सामाजिक परिणाम महत्वपूर्ण हैं। नशा मुक्त भारत अभियान- जागरूकता, शिक्षा और सामुदायिक कार्रवाई वाला एक राष्ट्रीय अभियान है। सीमा नियंत्रण और नारकोटिक्स ब्यूरो (एनसीबी)- बढ़ते नशीली दवाओं एवं नशे उत्पादों की तस्करी से निपटता है। यह नशीली दवाओं की जब्ती और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर काम करता है। नशे एवं ड्रग्स के धंधे की रोकथाम एवं जन-जागृति के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में उल्लेखनीय उपक्रम किये हैं, नयी-नयी योजनाओं को लागू किया है। मोदी सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार लोगों के कल्याण, नशामुक्ति एवं नशामुक्त भारत को निर्मित करने के प्रतिबद्ध है।

पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद की ही तरह नशे एवं ड्रग्स को व्यापक स्तर पर फैलाया है, जिसके दुष्परिणाम विशेषतः पंजाब के साथ-साथ समूचे देश को भोगने को विवश होना पड़ रहा है। पंजाब नशे की अंधी गलियों में धंसता जा रहा है, सीमा पार से शुरू किए गए इस छद्म युद्ध की कीमत पंजाब की जनता को चुकानी पड रही है, देर आये दुरस्त आये की भांति लगातार चुनौती बने नशीली दवाओं एवं ड्रग्स के धंधे के खिलाफ आप सरकार ने एक महत्वाकांक्षी युद्ध एवं अभियान शुरू किया है। दरअसल, सबसे बड़ा संकट यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में हेरोइन उत्पादन के केंद्र- गोल्डन क्रिसेंट के निकट होने के कारण पंजाब लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जूझ रहा है। पंजाब के 26 प्रतिशत युवा चरस, अफीम तथा कोकीन व हेरोइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स लेने में लिप्त हैं। पंजाब देश में ड्रग्स में सर्वाधिक संलिप्त राज्यों में आता है। यह डाटा गतदिनों गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 'मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा' पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में सामने आया।

पंजाब में नशे की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट भी चिन्ता व्यक्त करता रहा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व में 'ड्रग्स-फ्री इंडिया' अभियान चलाने की बात कहकर इस राष्ट्र की सबसे घातक बुराई की ओर जागृति का शंखनाद किया है। देश के युवा अपनी अमूल्य देह में बीमार फेफड़े और जिगर सहित अनेक जानलेवा बीमारियां लिए एक जिन्दा लाश बने जी रहे हैं, पौरुषहीन भीड़ का अंग बन कर। ड्रग्स के सेवन से महिलाएं बांझपन का शिकार हो रही हैं। पुरुषों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। नशे के ग्लैमर की चकाचौंध ने जीवन के अस्तित्व पर चिन्ताजनक स्थितियां खड़ी कर दी है। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन, तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुप्तावस्था में हो जाता है। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है। नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है या अपराध की अंधी गलियों में धंसता चला जाता है, पाकिस्तान युवाओं को निस्तेज करके एक नये तरीके के आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के चक्र को तोड़ने के लिए समन्वित दीर्घकालिक कार्रवाई की आवश्यकता है। जरूरत है दुनिया की इस बड़े संकट एवं नासूर बनती इस समस्या को जड़मूल से समाप्त करने के लिये सरकारों के साथ गैर-सरकारी संगठन कमर कसे।

प्रेषक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में उत्तर प्रदेश सचिवालय के विशेष सचिव डॉ. दीपक कोहली द्वारा लिखित पुस्तक 'नई दुनिया: नई तकनीक' का विमोचन किया। राज्यपाल जी को पुस्तक के लेखक डॉ. कोहली ने बताया कि इस पुस्तक में आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं जैसे बायोरॉक, डिजिटल ट्विन, नवप्रवर्तनकारी तकनीक, क्रिस्पर, स्वच्छ, फिनटेक, डीफेक, आधुनिक कृषि, एडटेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि की सरल और सहज भाषा में विस्तृत जानकारी दी गई है। तथ्यात्मक, सटीक और उपयोगी जानकारियों से युक्त यह पुस्तक तकनीक के बदलते स्वरूपों को समझने में सहायक है और विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, अध्यापकों के साथ-साथ आम जन मानस के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। इस अवसर पर डॉ. दिनेश चन्द्र अवस्थी (सेवानिवृत्त विशेष सचिव), श्रीमती रिम्मी कोहली (सी0एम0एस0, गोमतीनगर), श्री अक्षत कोहली (आई0टी0 इंजीनियर), एवं श्री अजय सिंह (निजी सचिव) भी उपस्थित थे।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किया विशेष सचिव डॉ. दीपक कोहली की पुस्तक 'नई दुनिया: नई तकनीक' का विमोचन

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में उत्तर प्रदेश सचिवालय के विशेष सचिव डॉ. दीपक कोहली द्वारा लिखित पुस्तक 'नई दुनिया: नई तकनीक' का विमोचन किया। राज्यपाल जी को पुस्तक के लेखक डॉ. कोहली ने बताया कि इस पुस्तक में आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं जैसे बायोरॉक, डिजिटल ट्विन, नवप्रवर्तनकारी तकनीक, क्रिस्पर, स्वच्छ, फिनटेक, डीफेक, आधुनिक कृषि, एडटेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि की सरल और सहज भाषा में विस्तृत जानकारी दी गई है। तथ्यात्मक, सटीक और उपयोगी जानकारियों से युक्त यह पुस्तक तकनीक के बदलते स्वरूपों को समझने में सहायक है और विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, अध्यापकों के साथ-साथ आम जन मानस के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। इस अवसर पर डॉ. दिनेश चन्द्र अवस्थी (सेवानिवृत्त विशेष सचिव), श्रीमती रिम्मी कोहली (सी0एम0एस0, गोमतीनगर), श्री अक्षत कोहली (आई0टी0 इंजीनियर), एवं श्री अजय सिंह (निजी सचिव) भी उपस्थित थे।

पंचायत चुनाव में उत्तराखंड का जनाक्रोश झेलेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा 2025 पंचायत चुनाव

प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी (युवा मोर्चा) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उत्तराखंड, आज एक बार फिर पंचायत चुनावों से चर्चा में है। इस बार का माहौल पहले से अलग है। जनता में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के प्रति गहरा जनाक्रोश दिखाई दे रहा है। आज़ादी के 78 वर्षो तक उत्तराखंड ने भाजपा और कांग्रेस को बार-बार मौका दिया, लेकिन बदले में उत्तराखंड को कुशासन और भ्रष्टाचार ही मिला।

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है। युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं मूलनिवासियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। जल जंगल और ज़मीन पर अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान होकर ज़नता ने बीजेपी को विकल्प चुना लेकिन आज बीजेपी ही ज़नता को बार-बार छल रही है और बार-बार मुख्यमंत्रियों के बदलने से जनता भी भ्रम की स्थिति में है 2021 में ही चार महीने में तीन मुख्यमंत्री बदले गए।

लेकिन अब तीसरे विकल्प में आम जनता की अपेक्षाएं हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प में आए और उन्हें बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाएं, रोजगार के अवसर दे। आम जन पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रिवर्स पलायन जैसे मुद्दों पर लामबंद है। परंतु दुर्भाग्यवश, आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने इन आम वादों पर नाकाम रही।

ये पंचायत चुनाव 2027 के सेमीफाइनल के रूप में होंगे। इसके लिए आम जनता अब आम आदमी पार्टी के झाड़ू बटन को दबाने के लिए तैयार है, आम जनता को अब आम आदमी के साथ होकर अपने बच्चों के भविष्य को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गिद्ध नजर से बाहर निकालना होगा। लाखों लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर उत्तराखंड में माफिया राज और जंगलराज को ख़त्म कर एक नई सुबह और नया भविष्य लाने के लिए संकल्पबद्ध है ।

स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर दिया जाए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावाः नरेंद्र बिंद्रा

श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उत्तराखंड वन विभाग प्रमुख श्री समीर सिन्हा से मुलाकात की

श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उत्तराखंड राज्य के वन विभाग के नव नियुक्त प्रमुख (HOFF) श्री समीर सिन्हा से भेंट की और उन्हें इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्ति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। यह मुलाकात उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंट साहिब के प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रही।

फूलों की घाटी, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अपनी अनूठी जैव-विविधता और दुर्लभ हिमालयी फूलों के लिए जानी जाती है। यह घाटी चमोली जिले में स्थित है और हर वर्ष हजारों पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। वहीं, श्री हेमकुंट साहिब, समुद्र तल से लगभग 4,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, सिख समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने तपस्या की थी। यह स्थल अपनी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है।

श्री समीर सिन्हा ने इस क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए फूलों की घाटी और श्री हेमकुंट साहिब यात्रा के सुधार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विशेष रूप से, भ्यूंडार घाटी में ईको-डेवलपमेंट कमेटी (EDC) के गठन में उनकी भूमिका ने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। उनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने तीर्थयात्रा और पर्यटन को और अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण मदद की है।

बैठक के दौरान, ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री सिन्हा ने क्षेत्र में बढ़ती पर्यटक संख्या के प्रबंधन और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने वैकल्पिक मार्गों, बेहतर बुनियादी ढांचे, और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया ताकि फूलों की घाटी और श्री हेमकुंट साहिब की प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित रखा जा सके। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और मजबूत कर पर्यटन और तीर्थयात्रा को अधिक सुगम और टिकाऊ बनाना था। श्री हेमकुंट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट इस क्षेत्र की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड वन विभाग के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्तराखंड सरकार आगामी कांवड़ मेले को सरल, सुखद व सुरक्षित संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध: मुख्य सचिव

इंटरस्टेट समन्वय समिति की बैठक सीसीआर सभागार हरिद्वार में संपन्न

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आगामी कांवड़ मेले को सरल, सुखद व सुरक्षित संपन्न कराने हेतु इंटरस्टेट समन्वय समिति की बैठक सीसीआर सभागार हरिद्वार में संपन्न हुई। जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के उच्चाधिकारियों द्वारा ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने कहा कि कांवड़ मेला आस्था एवं श्रद्धा का बहुत बड़ा उत्सव है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सकुशल एवम् सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य सम्बन्धित विभाग चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने सभी राज्यों से रियल टाइम कॉर्डिनेशन व रियल टाइम डाटा साझा किए जाने की बात भी कही। सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक इनपुट्स साझा किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं में आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए सभी तैयारियों को अंजाम दिया जाए ताकि मेले के अनुभव कुंभ में भी काम आएं। मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर भेल पार्किंग का भी उपयोग किए जाने के निर्देश भी जिला प्रशासन को दिए। यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन हो, साथ ही रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए।

डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि हर आयोजन नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि आस्था एवं श्रद्धा के इस मेले को सुरक्षात्मक रूप से संपन्न कराने हेतु रियल टाइम सूचनाएं साझा की जाए, किसी भी प्रकार की अफवाह का यूनिफाइड खंडन किया जाए। अपने कार्यों में दक्षता रखने वाले कर्मी ही एक-दूसरे स्टेट भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की जानकारी यात्रा मार्गो पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए। इंटर स्टेट कॉर्डिनेशन की अपेक्षाएं पूर्ण हों तथा मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो।

बैठक में सचिव गृह श्री शैलेश बगौली ने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, यातायात व्यवस्था सरल सुगम व सुरक्षित हो तथा श्रद्धालुओं की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित तथा एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कांवड़ यात्रा अवधि, विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रतिशत, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सहित कांवड़ यात्रा हेतु की जा रही तैयारियों का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की ओर से डीआईजी अभिषेक ने यात्रा प्लान सहित चल रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक सूचनाएं तथा इनपुट्स रियल टाइम साझा किए जाएं, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाए और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही के लिंक भी साझा किया जाए। कांवड़ 10 फीट से अधिक ऊंचाई के न हों। शराब तथा मीट से संबंधित एसओपी का सख्ती से अनुपालन हो, सभी चिन्हित डीजे संचालकों को नियमानुसार नोटिस देते हुए बाउण्ड ऑफ किया जाए। उत्तराखंड द्वारा समय-समय पर हरिद्वार में पार्किंग की स्थिति से उत्तर प्रदेश को अवगत कराया जाए।

बैठक में उत्तर प्रदेश से एडीजे भानु भास्कर, सचिव गृह मोहित गुप्ता, कमिश्नर मेरठ डिवीजन ऋषिकेश भास्कर यशोद, कमिश्नर बरेली सौम्य अग्रवाल, कमिश्नर सहारनपुर एके राय, डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह, आईजी आरपीएफ पंकज गंगवार, उत्तराखंड से आईजी निलेश आनंद भरणे, एनएस नपलच्याल, डीआईजी धीरेन्द्र गुंज्याल, एसएसपी देहरादून अजय सिंह, मेलाधिकारी सोनिका, सहित पांचों राज्यों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- विद्यार्थियों का इंटरव्यू या करियर से जुड़ी परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान रहेगा। किसी तरह की उलझन की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए सही रहेगी। विरोधियों की हरकतों पर भी ध्यान रखें। व्यस्त रहने के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना घर के माहौल को खुशनुमा रखेगा। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 9

वृषभ राशि- कामकाज से जुड़े सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे लेकिन अभी ज्यादा फायदे की उम्मीद न करें और गैरकानूनी काम में शामिल न हों। युवा लोग विपरीत लिंग के दोस्तों से बात करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। अपने हौसले को मजबूत बनाने के लिए ध्यान का सहारा लें।
भाग्यशाली रंग- हल्का नीला, भाग्यशाली अंक- 1

मिथुन राशि- घर में किसी रिश्तेदार का आना होगा। समय के हिसाब से अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। गुस्सा और नाराजगी जैसे बुरे स्वभाव पर नियंत्रण रखें। कोई दफ्तरी यात्रा संभव है। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में पड़कर अपनी पढ़ाई और करियर के साथ कोई समझौता न करें। स्वास्थ्य में लापरवाही न करें। भाग्यशाली रंग- गहरा पीला, भाग्यशाली अंक- 3

कर्क राशि- आप अपने आत्मविश्वास और हौसले के दम पर किसी खास लक्ष्य को पाने में सफल रहेंगे। कोई कोर्ट का मामला चल रहा है, तो सोच-समझकर काम लेने की जरूरत है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। घर में बच्चे के रोने की आवाज आने से खुशी का माहौल रहेगा। नकारात्मक बातों को हावी न होने दें। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 2

सिंह राशि- धार्मिक जगह पर कुछ समय बिताने से शांति मिलेगी और आपके व्यक्तित्व में अच्छा बदलाव आएगा। युवा लोग अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे। व्यवसाय में लोगों से मिलना और मार्केटिंग से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल रहने से खुशी का माहौल रहेगा। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 6

कन्या राशि- भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान रहेगा। उधार दिया हुआ या कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इसलिए कोशिश करते रहें। कुछ समय बच्चों के लिए भी निकालना जरूरी है। इस समय किसी भी तरह का खतरा न लें, आपके साथ धोखा हो सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार भरा रिश्ता रहेगा। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 9

तुला राशि- आज सोचने-विचारने और अपने अंदर झांकने का समय है। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ बहस होने से घर के माहौल पर भी बुरा असर पड़ेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को अचानक ही कोई खास काम करने का आदेश आ सकता है। पति-पत्नी के बीच कुछ अनबन रहेगी। मौसम से अपना बचाव करना जरूरी है। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 9

वृश्चिक राशि- धार्मिक कामों में भी आपका खास योगदान रहेगा। आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए अपने खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगी और व्यवसाय से जुड़ी बातें भी होंगी। पति-पत्नी के बीच पैसों के मामलों को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 7

धनु राशि- आपका बात करने का तरीका दूसरों को अपनी ओर खींचेगा। परिवार और व्यवसाय दोनों जगह अच्छा तालमेल बना रहेगा। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अच्छी है। इसका पूरा फायदा उठाएं। अपने हर काम में जीवनसाथी की सलाह फायदेमंद होगी। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 4

मकर राशि- परिवार के साथ घूमने-फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंता रह सकती है। व्यवसाय में अभी कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें। कोई रुका हुआ पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा समय पर मिल जाएगा। रिश्तों में नज़दीकी आएगी। घूमने-फिरने का प्रोग्राम भी बनेगा। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 3

कुंभ राशि- आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। कुछ समय बच्चों की परेशानियों को समझने और हल करने में भी जरूर लगाएं। विदेश से जुड़े व्यवसाय में अभी कुछ मंदी का असर बना रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा काम का बोझ रहेगा। प्रेम संबंधों में और ज्यादा नज़दीकी बढ़ेगी। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 9

मीन राशि- प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री से जुड़ा काम करने के लिए समय अच्छा है। धर्म और अच्छे कामों में भी रुचि रहेगी। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। गुस्सा और जल्दबाजी करना नुकसानदायक रहेगा। मार्केटिंग से जुड़े कामों में नुकसान होने की संभावना है, आज इन्हें टाल दें। एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 6

जब फिल्म साइन की, तब सिचुएशन ठीक थी: दिलजीत दोसांझ

विवादों के बीच दिलजीत दोसांझ का बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिया गया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हानिया आमिर के साथ काम करने और फिल्म को भारत में रिलीज न करने पर पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है, 'जब ये फिल्म बनी थी, तब सिचुएशन ठीक थी। जब हमने फरवरी में शूट की, तब सिचुएशन ठीक थीं। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। प्रोड्यूसर्स ने तय किया कि ये जाहिर तौर पर इंडिया में रिलीज नहीं होगी, तो इसे ओवरसीज रिलीज करते हैं। उनके दिमाग में था कि नुकसान तो होगा ही, क्योंकि एक टेरिटरी आप हटा रहे हैं। हानिया आमर के साथ काम करने पर दिलजीत ने कहा, 'वो बहुत प्रोफेशनल हैं। जब हम काम कर रहे थे, तो इतना टाइम नहीं था। मैं उनके काम की बहुत इज्जत करता हूं। मैं हमेशा हर किसी की प्राइवेसी की इज्जत करता हूं। मैं खुद बहुत प्राइवेट हूं, तो मैं दूसरों को भी स्पेस देता हूं। खासकर लड़कियों की। हमारी टू द पॉइंट ही बात होती थी।' मीका सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, 'दोस्तों देश पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही से बर्ताव कर रहे हैं। सरहद पार के किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने से पहले उन्हें दो बार सोचना चाहिए, खासकर जब इसमें हमारे देश की गरिमा की बात हो।' आगे मीका सिंह ने लिखा है, 'एक फिल्म थी, जिसमें फवाद खान (पाकिस्तानी एक्टर) और वाणी कपूर थीं, हम सबने मिलकर उसका विरोध किया था। लेकिन लगता है अब भी कुछ लोगों को सबक नहीं मिला है। सबसे ज्यादा शॉक की बात ये है कि एक फेक सिंगर जिसने भारत में 10 शोज किए, जिसमें हजारों फैंस ने उनके टिकट्स खरीदे, अब गायब हो चुका है। वो फैंस को धोखा देकर असहाय छोड़कर चला गया।' फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इम्प्लॉइज (FWICE) ने दिलजीत दोसांझ, प्रोड्यूसर गुनीर सिंह सिद्धू, मनमॉर्ड सिद्धू, और डायरेक्टर अमर हुंदल को देशद्रोही बताते हुए उन्हें इंडस्ट्री से बैन करने की मांग की है। FWICE ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से इन चारों के पासपोर्ट जब्त करने और इनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि इन लोगों ने न सिर्फ देश की भावनाओं का अपमान किया है, बल्कि पाकिस्तानी कलाकारों पर लगाए गए बैन का भी खुला उल्लंघन किया है। FWICE ने कहा कि हानिया आमिर केवल एक विदेशी कलाकार नहीं हैं, बल्कि वह भारत विरोधी विचारों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर भारतीय सेना का मजाक बना चुकी हैं और पाकिस्तान के आतंकी हमलों को सही ठहराने की कोशिश कर चुकी हैं। FWICE ने आरोप लगाया कि दिलजीत और उनकी टीम को इस बैन और हानिया आमिर के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने उन्हें कास्ट किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी निष्ठा भारत के साथ नहीं है।

FWICE बताया कि उसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड से यह मांग की थी कि फिल्म की भारत में रिलीज पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और उसे सर्टिफिकेट भी न दिया जाए। अधिकारियों ने उनकी बात और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान किया और इस फिल्म को भारत में रिलीज करने की इजाजत नहीं दी है। FWICE ने चेतावनी दी है कि जो भी भारतीय फिल्म निर्माता या कलाकार पाकिस्तानी नागरिकों के साथ काम करेगा, उसे देशद्रोह के बराबर माना जाएगा। साथ ही सभी OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, वितरकों और प्रदर्शकों से अपील की गई है कि वे इन चारों से सभी संबंध तोड़ लें।

बता दें कि विवादों के बीच दिलजीत ने सेंसर पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि लड़ाई अब शुरू हो रही है। दिलजीत ने अपनी पिछली विवादित फिल्म पंजाब 95 का भी जिक्र किया है, जो सेंसर बोर्ड की आपत्ति के चलते अब तक रिलीज नहीं हो सकी है।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

हिमालय का वरदान
बद्री गाय का घी

उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली बद्री गाय जिसको "कामधेनु" भी कहा जाता है, का परंपरागत रूप से बनाया गया घी अब देहरादून में भी उपलब्ध है

A2 प्रोटीन युक्त

औषधीय गुणों से भरपूर

इम्युनिटी बढ़ाने में लाभदायक

पाचन में हल्का और बाल विकास में सहायक

कुमार स्वीट्स

- सहस्त्रधारा रोड, निकट क्रॉसिंग
- धर्मपुर, निकट एलआईसी बिल्डिंग

पर उपलब्ध है।

fssai 22623030001586

UDYOG AADHAR MSME UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dehradun
Lokesh Asthana - 7409782771